माननीय राकेश कुमार जैन, जे. के समक्ष

डॉ. ममता राजोतिया-याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती. सुमन-प्रतिवादी

CR No. 5781 of 2014

16 दिसंबर 2014

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 33 नियम 1ए, 2, 3, 4, 5 और 6 - अकिंचन व्यक्ति- प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया - सिविल कोर्ट ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी गरीब व्यक्ति को दोषी ठहराया - याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सिविल कोर्ट ने एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन की अनुमति देकर गलती की, क्योंकि यह वादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि उसके वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह भी याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना - माना गया कि जहां अदालत को एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, वह विपरीत पक्ष और सरकारी वकील को कम से कम 10 दिन का स्पष्ट नोटिस प्रदान करके एक तारीख तय करेगा - चूँकि इस मामले में याचिकाकर्ता को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया, जिस आदेश के द्वारा प्रतिवादी को निर्धन व्यक्ति घोषित किया गया वह आदेश 33 नियम 3 सीपीसी के नियम 5 और 6 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अवैध था।

निर्णय, कि सीपीसी के आदेश 33 नियम 3 के अनुसार, एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब तक कि उसे अदालत में उपस्थिति से छूट न मिल जाए। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का

आवेदन वादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि यह उसके वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(पैरा 10)

आगे का निर्णय, जहां तक प्रतिवादी को नोटिस के सवाल का संबंध है, आदेश 33 नियम 6 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यदि न्यायालय को सीपीसी के आदेश 33 नियम 5 के संदर्भ में आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, तो वह एक तय करेगा विरोधी पक्ष और सरकारी वकील को ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 दिन का स्पष्ट नोटिस प्रदान करें जो आवेदक गरीबी के सबूत में पेश कर सकता है और साथ ही किसी भी सबूत को सुनने के लिए जो उसके खंडन में पेश किया जा सकता है। चूँकि प्रतिवादी को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना वादी को निर्धन व्यक्ति घोषित करने का आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध था।

(पैरा 12)

आगे का निर्णय, जैसा कि मैंने पहले ही देखा है कि सीपीसी के आदेश 33 नियम 3 के साथ नियम 5 और 6 का स्पष्ट उल्लंघन है और नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का कहना है कि गरीबी का प्रश्न केवल कार्यपालिका द्वारा तय किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा नहीं, यह भी स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि उक्त जांच सीपीसी के आदेश 33 नियम 1 ए के संदर्भ में की जानी है, जिसमें प्रावधान है कि पहली बार में, जांच न्यायालय के मुख्यमंत्री अधिकारी द्वारा की जानी है।

(पैरा 14)

बी.एस. गिरी, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए.*

राम अवतार श्योराण, एडवोकेट *प्रतिवादी के लिए.*

राकेश कुमार जैन, जे.

(1) प्रतिवादी-वादी ने 10,00,000/- रुपये की क्षति के लिए याचिकाकर्ता, जो एक डॉक्टर है, के खिलाफ जबरन और अनावश्यक समय से पहले प्रसव कराने, जिसके परिणामस्वरूप उसके बेटे की मृत्यु हो गई, के लिए मुकदमा दायर किया। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) के आदेश 33 नियम 2 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें 23.11.2012 को निम्नलिखित तरीके से एक आदेश पारित किया गया था। :-

> "उपस्थित: श्री. मांगे राम, वादी के लिए वकील.
>
> सूट आज मेरे सामने प्रस्तुत हुआ। चूंकि यह मुकदमा एक निर्धन व्यक्ति की हैसियत से दायर किया गया है इसलिए दरिद्र आवेदन की जांच कर उसे पंजीकृत किया जाए। एसडीएम, दादरी के माध्यम से कलेक्टर की कंगाली रिपोर्ट भी अलग से निर्धारित तिथि 12.01.2013 को या उससे पहले मंगवाई जाए।
>
> योगेश चौधरी
>
> एसीजे(एसडी), दादरी.
>
> 23.11.2012"

(2) अंततः पटवारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने बताया कि सुमन पत्नी अशोक कुमार पुत्र सतपाल, जाति जाट, स्थायी निवासी ग्राम मानकावास एक निर्धन व्यक्ति है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 09.01.2013 को सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा दिनांक 05.03.2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

> "आज, मामले को वादी की स्थिति के लिए विद्वान कलेक्टर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। बताया

गया है कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है। तहसीलदार, चरखी दादरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मद्देनजर, आवेदक को एक गरीब व्यक्ति घोषित किया जाता है। मुकदमे की जांच करने का आदेश दिया गया है. अब प्रतिवादी को 27.07.2013 के लिए नोटिस जारी किया जाए। पुराने मामले अधिक लंबित होने के कारण लंबी तारीख दी गई है।"

(3) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.03.2013 के एक पक्षीय आदेश को इस आधार पर रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि वादी को एक गरीब व्यक्ति घोषित करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने से पहले उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि पटवारी वादी को निर्धन व्यक्ति घोषित करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है और न ही उसने अपनी रिपोर्ट में कोई कारण बताया है। उक्त आवेदन का वादी ने विरोध किया था और दिनांक 08.05.2014 के आक्षेपित आदेश के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि सिविल कोर्ट इस तथ्य का निर्णय करने में सक्षम नहीं है कि वादी एक गरीब व्यक्ति है या नहीं, जिसका निर्णय केवल कार्यकारी पक्ष द्वारा ही किया जा सकता था।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि निचली अदालत ने सीपीसी के आदेश 33 नियम 6 के तहत आवश्यक प्रतिवादी/याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना वादी द्वारा एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति देकर गलती की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी, वादी द्वारा दायर एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाला आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि सीपीसी के आदेश 33 नियम 3 के तहत आवश्यक है और आदेश 33 नियम 5(ए) सीपीसी के मद्देनजर खारिज किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने **प्रेम सरदाना बनाम सावित्री देवी** [1] और **बीरेंद्र कुमार**

---

[1] 2001(1) Latest Judicial Report 103

बनाम मोहिंदर सिंह और अन्य [2] के मामले में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वादी को ठीक ही एक गरीब व्यक्ति घोषित किया गया है क्योंकि हल्का पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड की जांच की थी और उसे ऐसा घोषित किया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए मुकदमे के साथ दायर आवेदन वादी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है और सीपीसी के आदेश 33 नियम 2 के संदर्भ में सत्यापित है और वादी को अदालत आवेदन के साथ मुकदमा प्रस्तुत करने के समय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही अपनी ओर से एक वकील नियुक्त कर लिया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी को निर्धन व्यक्ति घोषित करने के समय प्रतिवादी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय शुल्क के भुगतान का प्रश्न नागरिक और राज्य के बीच है। इस संबंध में, उन्होंने **श्रीमती मंजुलता बनाम सिद्धकरण**[3] के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड की जांच की है।

(7) इसमें कोई विवाद नहीं है कि वादी और निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन पत्र एक ही दिन 22.11.2012 को तैयार किया गया था और ज़िमनी आदेश दिनांक 23.11.2012 के अनुसार, वादी और निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन पत्र वादी की ओर से श्री मांगे राम, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है

---

[2] 1985(2) PLR 612
[3] AIR 2005 Rajasthan 32

कि हलका पटवारी ने बिना कोई और विवरण दिए केवल यह रिपोर्ट दी है कि वादी एक गरीब व्यक्ति है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादी को निर्धन व्यक्ति घोषित करने से पहले प्रतिवादी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

(8) उपरोक्त तथ्यों के विवरण से, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

i. क्या वादी को निर्धन व्यक्ति घोषित करने से पहले न्यायालय को प्रतिवादी को नोटिस देना आवश्यक है?
ii. क्या वादी को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है?
iii. क्या एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है यदि यह सीपीसी के आदेश 33 नियम 3 के अनुसार दायर नहीं किया गया है?

(9) उपरोक्त प्रश्नों पर निर्णय लेने से पहले, सीपीसी के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"1ए. किसी निर्धन व्यक्ति की आय की जांच-

कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है या नहीं, इस प्रश्न की प्रत्येक जांच सबसे पहले, न्यायालय के मुख्य सचिव अधिकारी द्वारा की जाएगी, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, और न्यायालय ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट के रूप में अपना सकता है या स्वयं प्रश्न की जांच कर सकता है.

2. आवेदन की विषय-वस्तु - एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन में वादों के संबंध में आवश्यक विवरण शामिल होंगे; आवेदक की किसी भी चल या अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य के साथ एक अनुसूची उसके साथ संलग्न की जाएगी; और इसे अभिवचनों पर हस्ताक्षर

करने और सत्यापन के लिए निर्धारित तरीके से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

3. आवेदन की प्रस्तुति - इन नियमों में किसी बात के बावजूद, आवेदन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जब तक कि उसे न्यायालय में उपस्थित होने से छूट न दी गई हो, ऐसी स्थिति में आवेदन किसी अधिकृत एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, और जिसकी उसी तरह जांच की जा सकती है जैसे उसके द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी की जांच की जा सकती थी यदि ऐसी पार्टी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होती:

बशर्ते कि, जहां एक से अधिक वादी हों, वहां यह पर्याप्त होगा कि आवेदन किसी एक वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

4. xx xx xx

5. आवेदन की अस्वीकृति - न्यायालय एक निर्धन व्यक्ति के रूप में साइट की अनुमति के लिए एक आवेदन को अस्वीकार कर देगा -

(ए) जहां इसे नियम 2 और 3 द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार और प्रस्तुत नहीं किया गया है, या

(बी) जहां आवेदक एक गरीब व्यक्ति नहीं है, या

(सी) जहां उसने आवेदन प्रस्तुत करने से अगले दो महीने के भीतर किसी संपत्ति का धोखाधड़ी से निपटान कर दिया हो या एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन करने में सक्षम हो:

बशर्ते कि कोई भी आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा निपटाई गई संपत्ति के मूल्य को ध्यान में रखने

के बाद भी, आवेदक एक निर्‌धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का हकदार होगा, या

(डी) जहां उसके आरोप कार्रवाई का कारण नहीं दर्शाते हैं, या

(ई) जहां उसने प्रस्तावित मुकदमे की विषय-वस्तु के संदर्भ में कोई समझौता किया है, जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषय-वस्तु में हित प्राप्त किया है, या

(च) जहां आवेदक द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि मुकदमा उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा वर्जित होगा, या

(छ) जहां किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी को वित्तपोषित करने के लिए उसके साथ समझौता किया है।

6. आवेदक की निर्धनता का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन की सूचना.- जहां न्यायालय को नियम 5 में बताए गए किसी भी आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, वह एक दिन तय करेगा (जिसमें से कम से कम दस दिन की स्पष्ट सूचना) विपरीत पक्ष और सरकारी वकील को) दी जाएगी ऐसे सबूत प्राप्त करने के लिए जो आवेदन उसकी निर्धनता के सबूत में पेश कर सकता है, और किसी भी सबूत को सुनने के लिए जो उसके खंडन में पेश किया जा सकता है।

(10) सीपीसी के आदेश 33 नियम 3 के अनुसार, एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब तक कि उसे अदालत में उपस्थिति से छूट न मिल जाए। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि एक गरीब व्यक्ति के

रूप में मुकदमा करने का आवेदन वादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि यह उसके वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(11) बीरेंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि यदि एक गरीब व्यक्ति के रूप में आवेदन या मुकदमा वादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जब तक कि छूट न मिल जाए, तो आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उक्त दोष को मूल आवेदन में संशोधन द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश 33 नियम 5 (ए) में प्रावधान है कि यदि आवेदन नियम 2 और 3 के तहत निर्धारित तरीके से तैयार और प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उक्त आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(12) जहां तक प्रतिवादी को नोटिस देने का सवाल है, आदेश 33 नियम 6 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि न्यायालय को सीपीसी के आदेश 33 नियम 5 के संदर्भ में आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, तो वह एक तारीख तय करेगा। विरोधी पक्ष और सरकारी वकील को ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 दिन का स्पष्ट नोटिस प्रदान करके जो आवेदक गरीबी के सबूत में पेश कर सकता है और किसी भी सबूत को सुनने के लिए भी जो उसके खंडन में पेश किया जा सकता है। चूँकि प्रतिवादी को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए, वह आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा वादी को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना एक निर्धन व्यक्ति घोषित किया गया था, स्पष्ट रूप से अवैध था जैसा कि प्रेम सरदाना के मामले (सुप्रा) में आयोजित किया गया था जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश थे **श्री एम.एल.सेठी बनाम श्री आर.पी.कपूर**[4] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया है।

---

[4] AIR 1977 SC 2379

(13) जहां तक प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क का सवाल है कि कोर्ट फीस का भुगतान वादी और राज्य के बीच का मामला है, न कि प्रतिस्पर्धी पक्ष यानी प्रतिवादी/याचिकाकर्ता के बीच, तो उनके द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया **गया। श्रीमती मंजुलता का मामला (सुप्रा)** लागू नहीं है क्योंकि यहां इस मामले में सवाल यह है कि क्या वादी के आवेदन को एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने के लिए नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित आदेश सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं?

(14) जैसा कि मैंने पहले ही देखा है कि आदेश 33 नियम 3 के साथ पढ़े गए सीपीसी के नियम 5 और 6 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ कि गरीबी का प्रश्न केवल कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा नहीं, यह भी स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि उक्त जांच की जानी चाहिए सीपीसी के आदेश 33 नियम 1ए के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें प्रावधान है कि सबसे पहले, जांच न्यायालय के मुख्यमंत्री अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

(15) वर्तमान मामले में, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई रिपोर्ट है कि वादी एक गरीब व्यक्ति था जिसने सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय एक निजी नर्सिंग होम से इलाज कराने का आरोप लगाया था।

(16) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को योग्य पाया गया है और इसे स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा